भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2777

दिनांक 19 मार्च, 2021 को उत्तर दिये जाने के लिए

ओडिशा के कोरापुट जिले में काजू उद्योग पर संकट

2777. श्री अश्वनी वैष्णव:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ओडिशा के कोरापुट जिले में काजू उद्योग में आए संकट का संज्ञान लिया है;
(ख) क्या सरकार का काजू उद्योग को बचाने के लिए एक व्यापक योजना की शुरूआत करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;
(ग) क्या सरकार के ध्यान में यह आया है कि ओडिशा राज्य में काजू उद्योग कच्चे काजुओं की अनुपलब्धता के कारण बंद हुए हैं; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इन उद्योगों को कच्चे काजुओं की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (घ) : विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित विकासों और रूझानों पर जानकारी प्राप्त करना और उन पर उपयुक्त कार्रवाई करना एक सतत प्रक्रिया है। हालांकि, काजू उद्योग की सुरक्षा के लिए वर्तमान में कोई व्यापक स्कीम आरंभ करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत काजू और कोको विकास निदेशालय कच्ची काजू गिरी की मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को पाटने के लिए काजू का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठा रहा है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के अंतर्गत काजू की खेती, विशेषकर पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में, का व्यापक विस्तार करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता दी गई है। भारत सरकार के राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) ने देश में काजू विकास पर विशेष ध्यान दिया है और कच्ची गिरी के उत्पादन में वृद्धि हुई है। नवीन बागान विकास, जीर्ण शीर्ण बागानों का पुन:रोपण, नर्सरी की स्थापना और स्तरोन्नयन और प्रौयोगिकी कार्यक्रमों का हस्तांतरण जैसे कार्यक्रम एनएचएम/एमआईडीएच के अंतर्गत प्रमुख कार्यक्रम हैं। वर्ष 2005-06 से 2019-20 तक, उड़ीसा राज्य में 89,008.22 हैक्टेयर क्षेत्रफल सहित, देश में कुल 3,26,410.76 हैक्टेयर क्षेत्रफल को नव रोपण/पुन:रोपण/पुनर्जीवन कार्यक्रमों के अंतर्गत लाया गया है।

*****